RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 327
दि. 31.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च 2026 को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में सुबह लगभग 10 बजे सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सानंद में स्थित केयन्स सेमीकॉन प्लांट का दोपहर लगभग 12:45 बजे उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री वाव-थराद जाएंगे, जहां शाम लगभग 4 बजे, वे 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री का गांधीनगर दौरा

महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। अशोक के पौत्र और जैन परंपरा में अहिंसा के प्रति समर्पण तथा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए प्रसिद्ध सम्राट सम्प्रति के नाम पर स्थापित यह संग्रहालय जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करता है।

महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थित इस संग्रहालय में सात अलग-अलग खण्ड हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की सभ्यतागत परंपराओं के अनूठे पहलुओं को समर्पित है। यह आगंतुकों को सदियों पुराने ज्ञान और विरासत की एक व्यापक यात्रा के दर्शन कराता है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनों को आधुनिक डिजिटल और ऑडियो-विजुअल उपकरणों के साथ एकीकृत करता है, जिससे आगंतुकों, शोधकताओं और विद्वानों के लिए एक गहन और आकर्षक अनुभव का निर्माण होता है।

यह संग्रहालय सदियों पुराने दुर्लभ अवशेषों, जैन कलाकृतियों और पारंपरिक विरासत संग्रहों का संरक्षण और प्रदर्शन करता है। इनमें जटिल रूप से गढ़ी गई पत्थर और धातु की मूर्तियां, विशाल तीर्थ पट्टा और यंत्र पट्टा, लघु चित्रकारी, चांदी के रथ, सिक्के और प्राचीन पांडुलिपियां शामिल हैं।

जिन्हें सात भव्य दीघाओं में प्रदर्शित किया गया है। विशाल कक्षों में व्यवस्थित दो हजार से अधिक दुर्लभ खजानों से युक्त यह संग्रहालय आगंतुकों को जैन धर्म के विकास और इसके गहन सांस्कृतिक प्रभाव की कालानुक्रमिक समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

प्रधानमंत्री का सानंद दौरा

प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सानंद जीआईडीसी में स्थित केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत होगी, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल (आईपीएम) के निर्माण से होगी, जो ऑटोमोटिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं और जिन्हें कॉम्पैक्ट, कुशल और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मॉड्यूल में 17 चिप्स होते हैं और इनकी आपूर्ति कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर (एओएस) को की जाएगी। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने पर, इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट होगी।

केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में से माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली दूसरी सेमीकंडक्टर सुविधा होगी।

यह परियोजना विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसके अंतर्गत भारत की दूसरी ओएसएटी/एटीएमपी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट/असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकिंग) इकाई उत्पादन चरण में प्रवेश कर रही है। यह परियोजना सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय मूल की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनी के प्रवेश का भी प्रतीक है, जिससे घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिलती है।

यह सुविधा स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग क्षमता के निर्माण में योगदान देगी, भारत के चिप इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करेगी और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगी।

प्रधानमंत्री का वाव-थारद दौरा

प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं।

प्रधानमंत्री 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाएगा, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री पक्की शोल्डर वाली चार लेन की इदर-बडोली बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे एनएच-754के के धोलावीरा-मौवाना-वाउवा-संतालपुर खंड (पैकेज-क्क) को दो लेन की पक्की शोल्डर वाली सड़क में अपग्रेड करने की भी आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से राजमार्ग बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, धोलावीरा जैसे पर्यटन स्थलों सहित प्रमुख क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री गांधीनगर-कोबा-एयरपोर्ट रोड पर भाईजीपुरा जंक्शन पर बनने वाले फ्लाईओवर सहित कई महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस फ्लाईओवर से यातायात की भीड़ कम होगी और इसके नीचे व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। गांधीनगर-कोबा-आरोदराम रोड पर स्थित पीडीपीयू जंक्शन पर भी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। गांधीनगर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली इस सड़क पर प्रतिदिन 140,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। यह फ्लाईओवर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सीएच-0 जंक्शन से एयरपोर्ट तक सुचारू और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 और उससे जुड़े 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के परिवहन हेतु संबद्ध पारेषण प्रणालियों सहित प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 3,650 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और पारेषण क्षमता को मजबूत करेंगी।

रेल क्षेत्र में, प्रधानमंत्री कनलस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना (28 किमी), राजकोट-कनलस दोहरीकरण परियोजना का एक भाग (111.20 किमी), और गांधीधाम-आदिपुर खंड (10.69 किमी) के चौगुने विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से रेल क्षमता में वृद्धि होगी, भीड़ कम होगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा और यात्रियों और माल की आवाजाही तेज होगी।

प्रधानमंत्री हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा गेज रूपांतरण परियोजना (54.83 किमी) का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में रेल संपर्क और यात्री आवागमन में सुधार होगा।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति 31 मार्च से एक अप्रैल तक बिहार और कर्नाटक का दौरा करेंगी

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 31 मार्च से एक अप्रैल, 2026 तक बिहार और कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगी।

राष्ट्रपति 31 मार्च को बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

श्रीमती मुर्मु एक अप्रैल को कर्नाटक के तुमकुरु स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में डॉ. श्री श्री शिवकुमार महास्वामी जी के 119वें जन्मदिन और गुरुवंदना समारोह में शामिल होंगी।

शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में रबी फसलों की 18 लाख टन से अधिक एमएसपी खरीद के लिए 11,698 करोड़ रु. से ज्यादा की मंजूरी

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में रबी 2025-26 सीजन के दौरान दलहनों एवं तिलहनों की रिकॉर्ड मात्रा को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जिससे लाखों किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत की जाएगी और इससे किसानों को औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी।

हरियाणाः चना और सरसों की एमएसपी पर खरीद

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए रबी 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर 13,082 मीट्रिक टन चना और 3,60,528 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की अनुमति दी है। यह खरीद पीएसएस के तहत की जाएगी और इन

स्वीकृतियों का कुल एमएसपी मूल्य 2,312.12 करोड़ रुपये से अधिक होगा जिससे हरियाणा के चना और सरसों उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।

उत्तर प्रदेशः चना, मसूर और सरसों के लिए बड़ी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के पीएसएस प्रस्ताव के तहत रबी 2026 सीजन के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन चने की एमएसपी पर खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए एमएसपी मूल्य 1,316 करोड़ रु. है। मसूर के लिए 6,77,000 मीट्रिक टन की पूर्ण मांग (100 प्रतिशत) को मंजूरी दी गई है, जिस पर 70,000 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से 4,739 करोड़ रु. का एमएसपी मूल्य बनेगा, जबकि सरसों के 5,30,000 मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा पर 62,000 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से 3,286 करोड़ रु. का एमएसपी मूल्य होगा।

कर्नाटकः कुसुम (सैफ्लावर) की पीएसएस के तहत खरीद

कर्नाटक में रबी 2025-26 सीजन के दौरान कुसुम (सैफ्लावर) फसल के लिए पीएसएस प्रस्ताव को श्री शिवराज सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है जिसके तहत 6,923 मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा में उपज एमएसपी पर खरीद की जाएगी। राज्य द्वारा भेजे प्रस्ताव में 25 प्रतिशत (6,923 मीट्रिक टन) मात्रा स्वीकृत की गई है। और 2025-26 के लिए कुसुम का एमएसपी 65,400 रु. प्रति मीट्रिक टन तय है, जिससे कुल एमएसपी मूल्य 45.27 करोड़ रु. बनता है।

तीनों राज्यों में किसानों को बड़ा फायदा

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए स्वीकृत पीएसएस प्रस्तावों के माध्यम से चना, मसूर, सरसों और कुसुम जैसी महत्वपूर्ण दलहनी और तिलहनी फसलों की एमएसपी पर वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित खरीद सुनिश्चित की जाएगी।

'कुर्सी से एक दिन तो जाना ही है'; जब सीएम योगी ने सुनाया नोएडा के अपशकुन वाला किस्सा, अखिलेश पर निशाना

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को अपशकुन बताए जाने वाले किस्से का एक बार फिर जिक्र किया। लगातार दो दिनों में दो बाद नोएडा के इस किस्से के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा गया। एक दिन पहले शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा आने से रोकने की घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि नोएडा को पहले की सरकारों ने लूट का एटीएम बना दिया, लेकिन उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। पीएम ने कहा था कि हमलोग नोएडा आए। आज नोएडा सबसे तेजी से विकसित होते शहरों की श्रेणी में शामिल हो गया है। वहीं, रविवार को नोएडा पर कुर्सी जाने वाले अपशकुन का जिक्र करते हुए तंज कसा।

अंधविश्वास न मानने की बात

सीएम योगी ने आरएमएल संस्थान में नवनियुक्त नर्सिंग अफसरों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान अंधविश्वास और आस्था को लेकर बड़ी बात कही।

सीएम ने कहा कि मेरे कपड़े को देखकर लोग मानते होंगे कि मैं अंधविश्वास को मानता होऊंगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि मैं आस्था में विश्वास करता हूं। सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता। नोएडा का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? क्या वहां सीएम नहीं जाते?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने सवाल किया, क्या नोएडा यूपी से बाहर है? इसके बाद मुझे बताया गया कि यह मान्यता है, वहां जाएंगे तो सीएम कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा कि कुर्सी से एक न एक दिन जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़ें? मैं वहां जरूर जाऊंगा और गया भी था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि उस दौरान अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे, जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? हमारे लिए संडे हो या मंडे, सब एक जैसे दिन होते हैं।

अखिलेश पर साधा निशाना

सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। दरअसल, अखिलेश यादव ने रविवार को दादरी में जनसभा के जरिए यूपी चुनाव 2027 के अभियान का शंखनाद किया। इस पर सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए वे नोएडा नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं। इन लोगों ने नोएडा के विकास के लिए बाधाएं खड़ी कीं, वे आज विकास की बात करते हैं।

चौथी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की नौका-एग्रे नौसेना में शामिल

(जीएनएस)।

कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आठ पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) में से चौथा, 'एग्रे', 30 मार्च 2026 को कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।

कोलकाता के जीआरएसई द्वारा भारतीय जहाजरानी रजिस्टर (आईआरएस) के वर्गीकरण नियमों के अनुसार इन एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी का डिजाइन और निर्माण किया गया है, जो स्वदेशी रक्षा जहाज निर्माण की सफलता को रेखांकित करता है।

लगभग 77 मीटर लंबे ये जहाज जलजेट द्वारा संचालित भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत हैं और अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और उथले पानी के सोनार से सुसज्जित हैं, जो पानी के नीचे के खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और उनसे निपटने में सक्षम बनाते हैं। इस जहाज के शामिल होने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी और बारूदी सुरंग रोधी क्षमताओं के साथ-साथ तटीय निगरानी में और वृद्धि होगी।

यह जहाज पूर्व के आईएनएस एग्रे का पुनरोद्धार है, जो 1241 पीई श्रेणी के गश्ती पोतों में से चौथा था और जिसे वर्ष 2017 में सेवामुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार यह प्रतिष्ठित विरासत वाले नामों को बनाए रखने की नौसेना की परंपरा को जारी रखता है।

एग्रे की डिलीवरी भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह जहाज घरेलू रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम की बढ़ती शक्ति और आयात पर निर्भरता कम करने के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

विधानसभा चुनाव और उपचुनाव 2026: 2.3 लाख से अधिक मतदाता घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाएंगे

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं तथा 6 राज्यों में उप-चुनावों के लिए 15 मार्च 2026 को चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। आयोग, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 60(सी) के अनुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं और मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को डाक मतपत्र के माध्यम से घर से मतदान (होम वोटिंग) की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करता है। ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना की तिथि से 5 दिन के भीतर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन करना होता है।*

दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी

पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा

(जीएनएस)।

भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने आज नई दिल्ली में जनगणना-2027 पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। पहली बार, जनगणना डिजिटल रूप में आयोजित की जाएगी, और पहली बार 'स्व-गणना' (री'I-एल्लर्थ्रे१ं३ड्ढल्ल) का विकल्प भी उपलब्ध होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठउ्टउ और दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्व-गणना और 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास जनगणना आयोजित की जाएगी।

भारत की जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियम, 1990 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। भारत की पिछली

जनगणना वर्ष 2011 में संपन्न हुई थी। जनगणना 2027 श्रृंखला की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी।

भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 आयोजित करने के आशय को 16 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 की 00:00 बजे होगी (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 की 00:00 बजे होगी)।

जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

पहला चरण – मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (ल्छड), जो अप्रैल से सितंबर, 2026 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में आयोजित की जाएगी।

इसके साथ ही मकान सूचीकरण कार्य से पूर्व 15 दिनों की स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस चरण में मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं तथा उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। पहले चरण के प्रश्न जनवरी 2026 में अधिसूचित किए जा चुके हैं।

दूसरा चरण – जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में आयोजित होगा)। उउढअ के निर्णयानुसार, इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। जनसंख्या गणना की सटीक तिथियां एवं प्रश्नावली समयानुसार अधिसूचित की जाएगी।

सम्पादकीय

लक्ष्य हासिल नहीं होता देख जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका?

पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की कोशिशें कमजोर पड़ती जा रही है। अमेरिका और ईंरान की युद्ध बंदी की शर्तें ऐसी हैं कि हमें नहीं लगता कि इन पर कोई भी झुकने को तैयार होगा। तो क्या अब अमेरिका मुंह छिपाने के लिए और अमेरिकी जनता को इस हिमाकत युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए जमीनी युद्ध पर उतर सकता है? अमेरिका और ईंरान दोनों ने ही अपने रुख और कड़े कर लिए हैं। अमेरिका पामि एशिया में और सैनिक भेजकर सैन्य तैनाती बढ़ाता चला जा रहा है। करीब 2500 मरीन कमांडों के साथ अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली पामि एशिया के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 पैराट्रूपर्स भेजे जा रहे हैं। दूसरा वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर भी 2300 मरीन कमांडों के साथ अप्रैल में पहुंच रहा है। इस तरह करीब 7000 अमेरिकी सैनिक इलाके में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 50 हजार सैनिक पहले से ही मध्य-पूर्व में मौजूद हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका वूटनीति के साथ जमीनी हमले समेत सभी विकल्प खुले रखना चाहता है। जानकारों का कहना है कि अगर वूटनीति नाकाम रहती है तो इन अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल मुख्य रूप से चार उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। पहला-ईंरान के मुख्य तेल निर्यात वेंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा या उसकी नाकाबंदी। इस द्वीप पर हाल में अमेरिकी सेना ने 90 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए। दूसरा—होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करना और उस रास्ते में जहाजों की आवाजाही को फिर शुरू करना। तीसरा—ईंरान के तटीय इलाकों पर कार्रवाईं और चौथा— उसके एटमी ठिकानों को सुरक्षित करना और ईंरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेना। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जमीनी जंग के मंसूबों के जवाब में ईंरान ने बड़ी तैयारी कर ली है।

ईंरान ने 10 लाख सैनिकों की फौज जुटाईं है। साथ ही ईंरान ने कसम खाईं है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईंरान की धरती पर युद्ध के लिए उतरते हैं तो उनके लिए हम यह पैसला ऐतिहासिक नरक तैयार कर देंगे। चलिए एक नजर इस बात पर डालते हैं कि अगर अमेरिका ईंरान पर अपने सैनिक उतार देता है और खार्ग द्वीप और ईंरान के दक्षिणी तेल भंडार पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो इससे ईंरान के तेल के निर्यात को लगभग पूरी तरह अलग-थलग किया जा सकता है। शायद इससे होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हो। अमेरिका इसके वुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता है। लेकिन ईंरान असंभावित युद्ध रणनीति (जैसे गुरिल्ला वॉर) का इस्तमाल करके इसके वुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रख सकता है। दोनों पक्षों में भारी सैन्य हताहत होते हैं और ईंरान में नागरिक हताहत होते हैं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। यह भी संभावना है कि अमेरिकी सेना सीमित या बड़े पैमाने पर ईंरान में पंस सकती है। उदाहरण के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान सामने हैं। सैन्य अभियान आसान रास्ता नहीं हो सकता है। यह कभी भी साफ-सुथरा अभियान नहीं हो सकता। ऐसे अभियान कभी भी पूरी तरह सफल नहीं होते और यही इस युद्ध की सच्चाईं है।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लखनऊ में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के सीएसआर कार्यक्रम का उद्घाटन किया

लखनऊ, 30 मार्च 2026: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने आज लखनऊ में अपना सीएसआर कार्यक्रम आयोजित किया, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी की ₹200 करोड़ की राष्ट्रीय सीएसआर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में यह पहल समूह के व्यापक राष्ट्रीय सीएसआर ढांचे के तहत राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन को दशार्ती है, जिसका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख उन्मूलन, आवास और पर्यावरणीय स्थिरता पर है।यह कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि, आमंत्रित अतिथि और स्थानीय समुदाय के सदस्य भी उपस्थित रहे।उत्तर प्रदेश में सीएसआर पहलें शिक्षा-केन्द्रित हस्तक्षेपों पर आधारित हैं, जिनके तहत राज्य भर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को 1,500 शैक्षणिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही, समूह की पहल के अंतर्गत भूख उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 9 शहरों में प्रतिदिन लगभग 3,200 भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, 144 माइक्रो-लर्निंग सेंटरों के माध्यम से 5,889 छात्रों को शिक्षा सहयोग दिया जा रहा है, तथा 332 पेयजल कुओं के निर्माण के माध्यम से 5,700 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक संरचित सामाजिक प्रभाव दृष्टिकोण के तहत संचालित किए जा रहे हैं।इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक ने कहा,'शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण पर केंद्रित प्रयास समाज को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की पहलें व्यक्तियों के लिए अवसर सृजित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सार्थक योगदान देती हैं।'मलाबार समूह के चेयरमैन एम. पी. अहमद ने कहा,'हमारी सीएसआर पहलें समुदायों में दीर्घकालिक और संरचित प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई हैं। उत्तर प्रदेश में लागू किए जा रहे ये कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का अभिन्न हिस्सा हैं, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इन पहलों का लाभ लाभार्थियों तक निरंतर और प्रभावी तरीके से पहुंचे।'राष्ट्रीय स्तर पर ₹200 करोड़ के सीएसआर आवंटन का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए माइक्रो-लर्निंग सेंटर और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा 'हंगर फ्री वर्ल्ड' परियोजना के तहत खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, 'ग्रैंडमा होम' जैसी आवास परियोजनाएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी निधि आवंटित की गई है।मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अपने सीएसआर ढांचे के तहत अपने शुद्ध व्यापारिक लाभ का 5% सामाजिक पहलों पर व्यय करता है। ये कार्यक्रम एरङ्क सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं और 'प्रथम' तथा 'थानल' जैसे संगठनों के सहयोग से लागू किए जाते हैं।देशभर में अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से समूह अब तक 18 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल चुका है, और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का विस्तार जारी है।

अदित का विश्वासघात अब परिवार से आगे बढ़कर देश के लिए खतरा बन गया है कलर्स के 'मंगल लक्ष्मी' में

कलर्स का पारिवारिक ड्रामा 'मंगल लक्ष्मी' अपने शानदार 700 एपिसोड पूरे करने जा रहा है और इसी मौके पर शो में एक बड़ा मोड़ आया है, जो भारतीय महिला की बदलती छवि को स्क्रीन पर दिखाता है। जो कहानी मंगल (दीपिका सिंह) की थी—एक ऐसी महिला की जो घर की चारदीवारी में अपनी पहचान, सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी—अब वह और बड़ा रूप ले चुकी है, देश की बेटी के रूप में। सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आता है जब अदित सक्सेना (नमन शॉ), मंगल का पूर्व पति और उसकी सबसे बड़ी भावनात्मक चुनौती, देश के लिए खतरा साबित होता है। जो कभी घरेलू लड़ाई थी, अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गई है। मंगल अपनी 'घरेलू' समझ और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने घर को ही इंटेलिजेंस ग्राउंड बना देती है अदित की हर गतिविधि पर नजर रखती है, उसके कमरे में गुप्त उपकरण लगाती है और बिना किसी को शक हुए उससे कई कदम आगे रहती है। उसका मिशन साफ है—देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अदित को कानून के कटघरे में खड़ा करना। माँ होने की जिम्मेदारी और कानून की रक्षा दोनों को संतुलित करते हुए मंगल साबित करती है कि घर के भीतर सीखी गई खूबियाँ जैसे ध्यान से देखना, धैर्य रखना, भावनाओं को समझना, मजबूती और मल्टीटास्किंग - ये साधारण गुण नहीं बल्कि देश की सेवा करने वाली असली ताकत हैं। अब सवाल यह है कि जब मंगल सच के करीब पहुँच रही है, तो क्या अदित उसकी मिशन को नाकाम कर पाएगा?

अदित के इस खतरनाक रूप पर बात करते हुए नमन शॉ कहते हैं, 'अदित घायल पुरुष अहंकार का प्रतीक है और अब उसने वह सीमा पार कर दी है जहाँ उसके कदमों के नतीजे पूरे देश पर असर डालते हैं। हाँ, उसकी यात्रा एक चोटिल अहंकार और नियंत्रण की चाह से शुरू हुई थी। पहले उसने अपने परिवार को धोखा दिया और अब वह पूरे देश को धोखा दे रहा है। यही बदलाव उसे और भी खतरनाक बना देता है। वह अपने कामों को सही ठहराता है, उसे लगता है कि वह सही है और यही उसे अप्रत्याशित बना देता है। मुझे सबसे दिलचस्प यह लगता है कि शो कैसे अदित और मंगल को आमने-सामने खड़ा करता है। जिस 'घरेलू' जगह को अदित कमतर समझता है, वही मंगल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अदित जहाँ हाई-स्टेक्स गेम खेल रहा है, वहीं मंगल अपनी सहज प्रवृत्तियों से उसे मात दे रही है। इस ट्रैक में देशभक्ति की एक मजबूत परत जुड़ती है, क्योंकि अब टकराव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय है। यही वजह है कि यह आमना-सामना इतना तीव्र है - क्योंकि यह सिर्फ मंगल बनाम अदित नहीं बल्कि उनके मूल्यों की लड़ाई है। 700 एपिसोड पूरे करना इस बात का सबूत है कि मंगल लक्ष्मी ने भारतीय घरों से गहरा भावनात्मक रिश्ता बना लिया है। यह नया दौर टीवी पर महिलाओं की छवि को और आगे बढ़ाता है - सिर्फ पालन-पोषण करने वाली नहीं, बल्कि फैसले लेने वाली, सुरक्षा देने वाली और बदलाव लाने वाली। अगर मंगल की यात्रा महिलाओं को और निडर, जागरूक और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा देती है, तो 'देश की बेटी' का यह नया अध्याय अपनी मंज़िल पा गया। हमें और भी 'देश की बेटियों' को आगे बढ़ने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

देखिए 'मंगल लक्ष्मी' हर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, सिर्फ कलर्स पर।

केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अनुवादिनी एआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

आयुर्वेद अनुसंधान 13 भाषाओं में उपलब्ध: केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अनुवादिनी एआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एआई अनुवाद साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक ज्ञान को भाषाई बाधाओं के परे सुलभ बनाएगा

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद की जानकारी को 13 भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा विकसित अनुवादिनी एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद ज्ञान को बडे पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, अनुवादिनी एआई सीसीआरएएस के अनुसंधान परिणामों और शैक्षिक सामग्रियों का हिंदी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करेगी।

सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रबीनारायण आचार्य और

कार्यकारी अधिकारी डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन उन्नत भाषा प्रौद्योगिकी और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ज्ञान के महत्वपूर्ण संगम को दशार्ता है।

अनुवादिनी एआई तकनीकी, वैज्ञानिक और शासन सम्बंधी ज्ञान को विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विश्वसनीय, शोध-आधारित जानकारी की सुलभता, भाषाई या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से परे नागरिकों तक सुनिश्चित करना है।

देश के 25 राज्यों में 30 संस्थानों के नेटवर्क के साथ, सीसीआरएएस आयुर्वेद विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रकाशित करता है। इसका एक प्रमुख प्रकाशन, सीसीआरएएस बुलेटिन, एक त्रैमासिक शोध पत्रिका है, जो अन्य सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री के साथ वर्तमान में मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। समझौता ज्ञापन के तहत, अनुवादिनी एआई इन शोध परिणामों और शैक्षिक संसाधनों के 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में सहायता करेगी, जिससे प्रामाणिक आयुर्वेद ज्ञान की पहुँच व्यापक जनसमुदाय तक बढ़ाने और भ्रामक सूचना को जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर, सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर रबीनारायण आचार्य ने कहा कि यह सहयोग आयुर्वेद अनुसंधान के परिणामों से न केवल अकादमिक समुदाय बल्कि देश भर के नागरिकों को उनकी संबंधित भाषाओं में लाभ पहुंचाने के लिए सीसीआरएएस की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर ने कहा कि अनुवादिनी एआई विशेष रूप से ऐसे सहयोगों का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया था, जहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ज्ञान को अधिक सुलभ, न्यायसंगत और सशक्त बनाने में मदद करती है।

भविष्य में विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। इसकी शुरूआत उन देशों की भाषाओं से होगी जहां सीसीआरएएस ने अकादमिक केन्द्र स्थापित किए हैं। इस पहल से प्रामाणिक आयुर्वेद ज्ञान की वैश्विक पहुंच का विस्तार होगा।

सावधान! 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे ये सीसीटीवी कैमरे, क्या आपके घर में भी लगा है 'चीनी जासूस'

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से हिकविजन और दहुआ जैसी दिग्गज चीनी सीसीटीवी कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाया है। 1 अप्रैल से इन कंपनियों के इंटरनेट से जुड़ने वाले कैमरों और उपकरणों की बिक्री पर रोक लग सकती है। भारत का मानना है कि इन कैमरों के जरिए डेटा चोरी और जासूसी का खतरा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।

दूसरी ओर, चीन ने इसे व्यापारिक भेदभाव बताया है। चीनी मीडिया का कहना है कि भारत बिना किसी ठोस सबूत के सुरक्षा के नाम पर उनकी कंपनियों को बाजार से बाहर निकाल रहा है। यह विवाद अब व्यापार और सुरक्षा के बीच एक बड़ी बहस बन गया है।

सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रतिबंध

भारत सरकार को डर है कि चीनी

कंपनियों के कैमरों में ऐसे चिपसेट और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो भारतीय डेटा को चुपके से चीन के सर्वरों पर भेज दें। चूंकि ये कैमरे इंटरनेट से जुड़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाना आसान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल उन्हीं कैमरों को मंजूरी मिलेगी जो पूरी तरह सुरक्षित होंगे और जिनमें संवेदनशील डेटा को विदेश भेजने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह कदम देश की डिजिटल सीमा को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है।

चीन ने बताया भेदभावपूर्ण कदम

चीनी सरकारी मीडिया 'ग्लोबल टाइम्स' ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं और यह सिर्फ चीनी कंपनियों को बाजार से हटाने की एक राजनीतिक चाल है। उनका दावा है कि ये कंपनियां पूरी दुनिया में व्यापार करती हैं और उनके उत्पाद सुरक्षित हैं। चीन के अनुसार, भारत तकनीकी मानकों के नाम पर व्यापार में रुकावटें पैदा कर रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों और निष्पक्षता के खिलाफ है।

भारतीय बाजार को ही नुकसान-चीन का तर्क

चीनी विशेषज्ञों का तर्क है कि इस प्रतिबंध से भारतीय बाजार को ही नुकसान होगा। उनका कहना है कि चीनी कंपनियां किफायती और एडवांस टेक्नोलॉजी देती हैं। उनके हटने से कैमरों की कीमतें बढ़ सकती हैं और बाजार में विकल्प कम हो जाएंगे। चीन का मानना है कि भारतीय कंपनियां अभी भी हाई-एंड टेक्नोलॉजी के लिए आयात पर निर्भर हैं, ऐसे में एकदम से चीनी सप्लाई चेन को तोड़ना भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ सकता है और विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है।

चीन का दावा है कि इस फैसले से भारतीय कंपनियों के 'आत्मनिर्भर' बनने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वे अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हालांकि, भारत का मानना है कि इस कदम से घरेलू कंपनियों को आगे आने का मौका मिलेगा। झांग शियाओरोंग जैसे चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी चिपसेट के बिना भारतीय कैमरों की विश्वसनीयता कम हो सकती है।

भारत को जल्द मिलेगा चौथा र-400 मिसाइल सिस्टम, सीमा सुरक्षा होगी और मजबूत, समझें दुश्मनों पर कैसे करेगा वार?

(जीएनएस)।

भारत की रक्षा क्षमता को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है, क्योंकि देश को अप्रैल के अंत तक रूस से चौथा s-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इस सिस्टम की डिलीवरी से भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी तथा खासकर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।

यह सिस्टम काफी एडवांस माना जाता है और दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों को दूर से ही पहचानकर उन्हें खत्म करने की ताकत रखता है।

दरअसल, भारतीय वायुसेना ने पहले ही रूस से पांच s-400 सिस्टम और पैंट्सिर शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव रखा था। पहले से मिले तीन s-400 सिस्टम अलग-अलग एरिया में तैनात किए जा चुके हैं, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा पहले ही काफी मजबूत हो चुकी है। अब चौथा सिस्टम आने के बाद खासकर पश्चिमी सीमा पर निगरानी और सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। वहीं पांचवा मई माह में भारत पहुंच जाएगा।

s-400 सिस्टम कैसे करता है सुरक्षा?

पैंट्सिर सिस्टम खास तौर पर ड्रोन, कामिकेज ड्रोन , जिन्हें लोइटरिंग मुनिशन या 'सुसाइड ड्रोन' भी कहा जाता है उन्हें और कम दूरी के हवाई हमलों को रोकने में बेहद कारगर माना जाता है। जब इसे s-400 जैसे लंबी दूरी के सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक मजबूत "दोहरी परत" वाली रक्षा ढाल तैयार करता है, जो सीमा पार से आने वाले हर तरह के हवाई खतरे को निशाना बना सकती है।

314 KM दूर से पाक के बड़े विमान को बनाया था निशाना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने एक s-400 मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करीब 314 किलोमीटर दूर एक बड़े विमान को निशाना बनाया था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई और उसने अपने ऑपरेशनल विमानों को पश्चिमी एयरबेस की ओर शिफ्ट कर दिया।

भारत की सुरक्षा रणनीति में गेमचेंजर साबित हो रहा

इतना ही नहीं, जब भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और पसूर में पाकिस्तानी रडार ठिकानों पर हमला किया, तब 9-10 मई को पाकिस्तानी वायुसेना की कोई खास गतिविधि नजर नहीं आई। खबरों के मुताबिक अदामपुर और भुज सेक्टर में तैनात s-400 सिस्टम के डर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कुल मिलाकर s-400 और पैंट्सिर जैसे आधुनिक सिस्टम भारत की सुरक्षा रणनीति में गेमचेंजर साबित हो रहे हैं।

एनसीएल ने समय से पहले हासिल किया 140 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य

(एजेंसी)।

सिंगरौली स्थित कोल इंडिया की प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 140 मिलियन टन कोयला उत्पादन के अपने वार्षिक लक्ष्य को समय से पहले 30 मार्च, 2026 (पहली पाली के बाद) को ही हासिल कर लिया है। अपनी 10 अत्याधुनिक मशीनीकृत खुली खदानों के साथ एनसीएल ने पिछले एक दशक से लगातार अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की अपनी विरासत को बनाए रखा है, जो इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को दशार्ता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी है।

वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य में घरेलू रूप से उत्पादित कोयले ने एक बार फिर देश के विद्युत क्षेत्र की विश्वसनीय आधारशिला के रूप में स्वयं को सिद्ध किया है। इस संदर्भ में एनसीएल का निरंतर और बढ़ा हुआ उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों को निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

इस उपलब्धि पर एनसीएल के प्रबंधन ने अटूट प्रतिबद्धता, दृढ़ता और अथक प्रयासों के लिए अपनी टीम (एनसीएल) के समर्पित प्रयासों और सहयोग के लिए सभी हितधारकों की सराहना की।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

भगवान महावीर जयंती पर निकली भव्य रथ यात्रा श्रद्धा-उल्लास का अद्भुत संगम

(एजेंसी)।

राजधानी लखनऊ /प्रयागराज

भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर शहर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। जैन समाज द्वारा भव्य रथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर भगवान महावीर के 1008वें जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया।

रथ यात्रा का भव्य दृश्य

जैन मंदिर से प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में सजे-धजे रथ पर भगवान वर्धमान महावीर के माता-पिता विराजमान थे। श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर यात्रा का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं के हाथों में धार्मिक ध्वज-पताकाएं लहरा रही थीं।

ढोल-ताशा, डीजे और पंजाबी बैंड की धुनों पर लोग झूमते नजर आए। आकर्षक झांकियां, ऐरावत हाथी, देवी-देवताओं के रूप में सजे कलाकार यात्रा का आकर्षण बने रहे। बग्घी में विराजमान वर्धमान के माता-पिता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सड़क के दोनों ओर खड़े श्रद्धालु हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए फूलों की वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत कर रहे थे।

श्रद्धा में रंगा शहर

महिलाएं और बच्चे पीले वस्त्रों में नजर आए, जिससे पूरा माहौल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सरसों के फूल लहरा रहे हों। 'बच्चा-बच्चा महावीर की जय बोलेगा, जैन धर्म की जय-जय बोलेगा' जैसे भजनों पर श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए नृत्य कर रहे थे।

महावीर के संदेशों का प्रसार

यात्रा के दौरान भक्तों ने भगवान महावीर के उपदेशों हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए, जियो और जीने दो, जीव-जंतुओं से प्रेम करें, गर्मी में पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करें को जन-जन तक पहुंचाया।

प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा

यह शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर बहादुरगंज, लोकनाथ, बजाज पट्टी, चौक घंटाघर, जॉनसेनगंज, एस.सी. वासु रोड होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंचकर पूरी हुई।

प्रमुख लोगों की उपस्थिति

इस भव्य आयोजन में दिनेश कुमार जैन, निर्मल जैन, राजेश जैन, अशोक जैन, आलोक जैन, मुनीन्द्र जैन, अमित जैन, राजू जैन, आकाश जैन, अर्पित जैन, विजय चौरसिया, अकरम शगुन सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।

सुरक्षा और व्यवस्था चाक-चौबंद

रथ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। एसीपी रवि कुमार गुप्ता, कोतवाली इंचार्ज संजय राय, बहादुरगंज चौकी, शाहगंज थाना सहित पुलिस बल, सभी ने सुबह से ही यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा पीस कमेटी के चांद मियां, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद डाबर, सिविल डिफेंस के अनु भैया, ताहिर अंसारी, राकेश मल्होत्रा, पूर्व पार्षद अनीस अहमद सहित अन्य लोगों ने भी सहयोग किया। भगवान महावीर जयंती पर निकली यह भव्य रथ यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि समाज को शांति, अहिंसा और प्रेम का संदेश भी देती नजर आई। पूरे शहर में भक्ति और सौहार्द का वातावरण देखने को मिला।

कृषि प्राविधिक सहायक (AGTA) भर्ती में आरक्षण, घोटाला को लेकर छात्रों में नाराजगी।

(एजेंसी)।

हरदोई। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में निकलीं भर्ती को लेकर जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रतिभागियों में नाराजगी बनीं हुईं हैं। सभी छात्रों का आरोप है कि विभाग द्वारा जो रिक्त पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है उसमें ओबीसी एससी एसटी वालों के साथ गलत किया जा रहा है कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2026 की भर्ती में जो विभाग द्वारा पदों का बंटवारा किया गया हैं उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। जिसमें जान बूझ कर सरकार द्वारा पदों की कटौती की गयी है। छात्रों का कहना हैं कि भाजपा सरकार जान बूझ कर आरक्षण में कटौती करके ओबीसी एससी एसटी वर्ग को कमजोर करने की साज़िश हो रही हैं। प्राप्त आरक्षण के अनुसार जनरल कोटा में ज्यादा पद होने को लेकर छात्रों में आक्रोश डेटा के अनुसार ईडब्लूएस 10% ओबीसी को 27% आरक्षण व एससी को 21% आरक्षण के हिसाब से बहुत बड़ा घोटाला किया गया हैं।

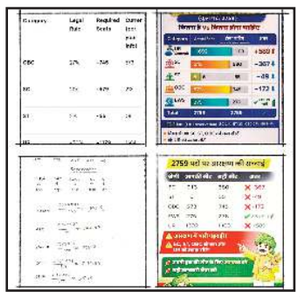

कुल पदों की संख्या 2759 हैं जिसमें की ओबीसी को 745 पद होने चाहिये थे जिसमें 172 पद कम हैं। जिसके बाद एससी पदों को गणना की गयी पाया गया कि जिसमें की 580 पद होने चाहिये थे जिसमें भी 367 पद कम हैं। एसटी वर्ग को भी 49 पद मिले जिसके बाद ईडब्लूएस पदों को देखा गया जिसमें 1 पद इधर उधार मतलब सही है भर्ती प्रकिया में जनरल वर्ग 1130 पद मिलने चहिये है जिसमें जनरल वर्ग को 1692 पद दिये गए जिसको लेकर जगह जगह छात्र द्वारा विरोध कर रहे। छात्र व संगठनों द्वारा ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं छात्रों का कहना हैं मुख्यमंत्री जी भेद भाव बंद करे। छात्र देख का भविष्य ही नहीं बल्कि आज के समय में राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते हैं बीजेपी सरकार पर छात्रों का निशाना प्रतिभागियों द्वारा बताया गया कि आगे आने वाला 2027 चुनाव कमजोर होता दिखाई दे रहा है जिसपे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

बिलसंडा ब्लॉक: सिसैया साहब में ग्राम निधि की लूट! बिना काम के उड़ाए लाखों, प्रधान पति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ग्रामीणों की शिकायतें दबाई गई

अब भाकियू के बैनर तले भ्रष्टाचार उजागर करने को तैयार

(एजेंसी)।

पीलीभीत जिले के बिलसंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिसैया साहब में ग्राम निधि के साथ बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम प्रधान शमीम बानो के पति पर इल्जाम है कि उन्होंने विकास के बहाने बिना कोई काम किए ग्राम निधि से लाखों रुपये गबन कर लिए। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में न विकास के निशान दिखते हैं, न खर्च का कोई ब्योरा सार्वजनिक हुआ। फिर भी खाते से लगातार पैसे निकाले जाते रहे, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क गया है।

खासतौर पर 25 मार्च 2026 को ग्राम निधि से भारी रकम संदिग्ध रूप से निकाली गई, जबकि कोई काम जमीन पर नहीं हुआ। ग्रामीण इसे सरकारी पैसों की खुली लूट बता रहे हैं। कई बार ब्लॉक अधिकारियों और विभागों को शिकायत की गई, मगर हर बार मामला रफा-दफा करने की कोशिश हुई। इससे स्थानीय स्तर पर साठगांठ की आशंका भी बढ़ गई है।

अब तंग आ चुके ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेताओं के पास पहुंचे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को सबके सामने लाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भाकियू नेताओं ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इसे उजागर कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

ग्राम निधि खाते की निष्पक्ष जांच।

दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई,गबन की गई राशि की वसूली,अगर जल्द जांच न हुई, तो यह मामला बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। अब प्रशासन पर नजरें टिकी हैं कि वह कार्रवाई करता है या भ्रष्टाचार को फिर ढकने की कोशिश करता है।

मिशन शक्ति 5.0 फेज-2: पीलीभीत के ग्राम सैदपुर में जागरूकता के लिए ग्रामसभा आयोजित

(एजेंसी)।

पीलीभीत। जनपद पीलीभीत में महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 फेज-2 के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 29 मार्च 2026 को ग्राम सैदपुर में हब से अजीत सिंह एवं श्रीकांत द्वारा ग्रामसभा का सफल आयोजन किया गया।

इस ग्रामसभा में ग्रामीणों को महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों एवं कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाना एवं मिशन शक्ति अभियान को गति प्रदान करना था। स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विभिन्न सवालों के माध्यम से अपनी जागरूकता बढ़ाई। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर जारी रहेगा।

मिशन शक्ति फेज-5.0: थानों पर महिला शक्ति केंद्र टीमों ने महिलाओं-बालिकाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति किया जागरूक

(एजेंसी)।

पीलीभीत/

30 मार्च 2026मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जिले के समस्त थानों पर नियुक्त महिला शक्ति केंद्र की टीमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने का सराहनीय कार्य किया। इस अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी किया गया।कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की। इनमें वूमेन पावर लाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, पुलिस

आपातकालीन सेवा-112, स्वास्थ्य सेवा-102/108, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, चाइल्ड लाइन-1098 एवं साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 प्रमुख रूप से शामिल हैं। पुलिस टीम ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल इन हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें, ताकि सहायता शीघ्र उपलब्ध हो सके।यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिले भर में चल रहे इस जागरूकता कार्यक्रम से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब अपनी सुरक्षा के लिए अधिक सजग हो रही हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं महिला शक्ति केंद्र टीमों ने बताया कि यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा, जिससे समाज में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ऑटिज्म एक्सपर्ट डॉ. प्रिंस कुमार को मिलेगा ब्रिटिश संसद में सम्मान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करेंगे शोध प्रस्तुति

बहराइच। जनपद के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है कि ऑटिज्म एवं बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ डॉ. प्रिंस कुमार (इलटर, टऊ) को 10 अप्रैल को लंदन स्थित ब्रिटिश संसद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

डॉ. प्रिंस कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय बहराइच के वर्ष 2007 बैच के छात्र रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली में सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। अपने उत्कृष्ट कार्यों और सेवाओं के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 'ऑटिज्म एवं बच्चों के व्यवहार में होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रभावशीलता' विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो होम्योपैथी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है।

डॉ. प्रिंस कुमार की इस उपलब्धि से पूरे बहराइच ज में खुशी की लहर है। उनके पिता श्री संतोष प्रधान, माता एवं पत्नी डॉ. निवेदिता सहित परिवार के सभी सदस्य इस सम्मान को लेकर अत्यंत गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके पैतृक निवास छावनी सरकार, बहराइच में उत्सव जैसा माहौल है और लोगों द्वारा लगातार बधाइयां दी जा रही हैं।

डॉ. प्रिंस कुमार की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले और नवोदय परिवार के लिए प्रेरणादायक है। यह सफलता दशार्ती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक सम्पन्न, रूपेश गंगवार बने बीसलपुर नगर अध्यक्ष

(एजेंसी)।

बीसलपुर में ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के अनेक पत्रकार साथियों ने भाग लिया। बैठक चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी की मौजूदगी में सम्पन्न हुई।बैठक के दौरान संगठन की मजबूती, पत्रकार हितों की सुरक्षा तथा भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी पत्रकार साथियों की सर्वसम्मति से रूपेश गंगवार को बीसलपुर नगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर अनुराग मिश्रा सारथी ने नव-मनोनित नगर अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। रूपेश गंगवार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन के हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे तथा पत्रकारों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएंगे।बैठक में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों ने नव-नियुक्त नगर अध्यक्ष का स्वागत किया और संगठन को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में तहसील कोर्डिनेटर प्रियंक पाठक, तहसील अध्यक्ष सुनील मिश्रा,तहसील उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, तहसील मीडिया प्रभारी दीनदयाल शास्त्री,शुभम राज सागर,रोहित मिश्रा,अनिल शर्मा, इलयास अहमद, रूपेश गंगवार, अमित दीक्षित, प्रदीप कुमार, मोहनस्वरूप,अमन अंसारी आदि लोग मौजूद रहे

मुंबई में डब्बावाला सेवाएं 6 दिनों के लिए बंद क्यों? चौंकाने वाली है वजह

(जीएनएस)।

मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली डब्बावाला सेवा अचानक 6 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। यह फैसला मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन ने लिया है। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक 6 दिनों के लिए पूरी टिफिन डिलीवरी सेवा अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है।

अब मुंबई और आसपास के लाखों ऑफिस-कॉलेज जाने वाले लोगों को अपना घर का खाना डब्बे में नहीं मिलेगा। आखिर क्या है बंद करने की वजह? आइए जानते हैं...

135 साल पुरानी परंपरा का सम्मान

डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तालेकर ने साफ कहा कि हम 135 साल से ज्यादा समय से मुंबई की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हर साल इस समय हम अपनी जड़ों में लौटते हैं। पुणे जिले के पश्चिमी इलाकों से आने वाले ज्यादातर डब्बावाले अपने पैतृक गांवों में जाकर ग्राम देवता की पूजा, पारंपरिक त्योहार और मेलों में शामिल होते हैं। ये छुट्टी कोई नई बात नहीं - बल्कि वार्षिक परंपरा है। डब्बावाले कहां-कहां जाते हैं?

अधिकांश डब्बावाले इन गांवों से आते हैं:

मावल, मुलशी, अंबेगांव, जुन्नार, खेड़, अकोले, संगमनेर

यहां वे सिर्फ पूजा-पाठ नहीं करते, बल्कि गांव के मेलों में शामिल होते हैं, परिवार से मिलते हैं और खेती-किसानी के कामों में भी हाथ बंटाते हैं। यही उनका असली घर और असली जिंदगी है।

लाखों लोगों पर असर - एलपीजी संकट में नई मुश्किल

मुंबई में जहां एलपीजी सिलेंडर का संकट पहले से ही लोगों को परेशान कर रहा है, उसी बीच डब्बावाला सेवा का 6 दिन का ब्रेक ऑफिस जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। जो रोज सुबह 9-10 बजे तक टिफिन मंगवाते थे, उन्हें अब वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे:-

घर से खाना पैक करना

बाहर से ऑर्डर करना

या कैंटीन का सहारा लेना

डब्बावालों की अपील

एसोसिएशन ने ग्राहकों से खास अनुरोध किया है कि पूरे साल हम बिना किसी रुकावट के सेवा देते हैं। इस छोटी सी छुट्टी के दौरान कृपया वेतन में कटौती न करें। आपका सहयोग हमें और मजबूती देगा।

यूपीपीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी, नेहा पंचाल बनीं टॉपर

(एजेंसी)।

राजधानी लखनऊ /प्रयागराज

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने रविवार देर रात पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार परीक्षा में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है।

टॉपर्स की सूची

पहला स्थान नेहा पंचाल, दूसरा स्थान अनन्या त्रिवेदी तथा तीसरा स्थान अभय प्रताप सिंह को मिला है। टॉप 10 में कुल 6 लड़कियां शामिल हैं, जो इस परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों की मजबूत भागीदारी को दशार्ता है। हालांकि, आयोग ने अभी तक टॉपर्स के गृह जनपद की जानकारी साझा नहीं की है।

चयन और पदों का विवरण

कुल 932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ।इनमें 37 डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम), 17 पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), 196 असिस्टेंट कमिश्नर (कमर्शियल टैक्स) शामिल हैं। वहीं व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक के 14 पद योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गए।

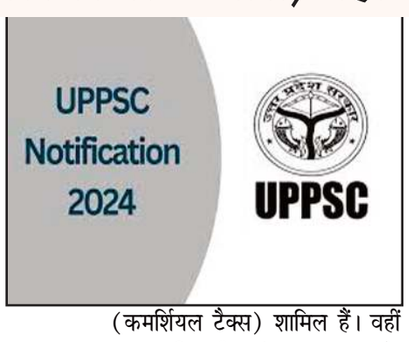

इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया

कुल 947 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इनमें से 2698 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। 21 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा का पूरा सफर

5.76 लाख उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स के लिए आवेदन किया। मार्च 2025 में प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हुआ।15,066 अभ्यर्थी मेन्स के लिए क्वालीफाई हुए। 13,776 अभ्यर्थी मेन्स परीक्षा में शामिल हुए। मेन्स परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच आयोजित की गई।

टांके लगे...शादी की खुशियां...'मौत का मंझा' बना आफतङ्क्युवक का गला रेता, आठ टांके लगे शादी की खुशियां गम में बदलीं

(एजेंसी)।

राजधानी लखनऊ /प्रयागराज

प्रयागराज

गंगानगर जोन के पुरानी झूंसी निवासी मोहम्मद साहिल के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। शाम करीब 6 बजे तक वह घर पर सजावट का काम देख रहा था,। फिर रविवार की शाम कपड़ा खरीदने के लिए साहिल शहर के लिए निकला। घर में खुशियों का माहौल था और महज 2-4 दिन बाद शादी होनी थी। शाम 7 बजे के लगभग जैसे ही वह गऊघाट ईसीसी कॉलेज के सामने पहुंचा एक पल में सब कुछ बदल गया। अचानक हवा में तना हुआ प्रतिबंधित चाइनीज मंझा सामने आ गया और मांझे ने साहिल की गर्दन को रेत डाला। बाइक चला रहे साहिल के मामा इम्तियाज ने तुरंत गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक पीछे बैठे साहिल की गर्दन में मंझा गहराई तक घुस चुका था। धार इतनी तेज थी कि गला में गहरा जख्म हो गया। खून से लथपथ हालत में साहिल को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गर्दन पर 8 टांके लगाए गए। किसी तरह उसकी जान बच सकी। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि प्रतिबंध के बावजूद शहर में चाइनीज मंझा खुलेआम बिक रहा है और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ लगातार हो रहा है। प्रयागराज की ये पहली घटना नहीं ऐसी घटना बराबर देखने को मिल रही है। सख्त प्रतिबंध के स्पष्ट आदेश के बाद भी चाइनीज मांझे का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। जरूरत है कि प्रशासन तुरंत सख्त कदम उठाए, अवैध रूप से मंझा बेचने वालों पर कार्रवाई करे। ताकि किसी और घर की खुशियां इस तरह हादसे में न बदलें।

खुलेआम बिक रहा 'मौत का मंझा'

प्रशासनिक प्रतिबंधों के बावजूद चाइनीज मांझा अभी भी खुलेआम बिक रहा है और जान के लिए खतरा बना हुआ है। इससे जमीनी स्तर पर लापरवाही साफ नजर आती है।

जरूरी सवाल!

प्रतिबंध के बावजूद यह खतरनाक मांझा बाजार में कैसे पहुंच रहा है? प्रशासन कब तक ऐसे हादसों का इंतजार करेगा ?कितनी और जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। जरूरत है कि अवैध मांझा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। बाजारों में सख्त निगरानी रखी जाए। आम जनता को भी जागरूक किया जाए, ताकि किसी और घर की खुशियां इस तरह खून में न बह जाएं।

साइबर ठगी का शिकार महिला को बड़ी राहतः पुलिस ने वापस कराए 5 लाख रुपये, कार्रवाई की सराहना

(एजेंसी)।

राजधानी लखनऊ /प्रयागराज

प्रयागराज। साइबर अपराध के खिलाफ गंगानगर की झूंसी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई एक महिला को झूंसी पुलिस की सक्रियता से उसके पूरे 5 लाख रुपये वापस मिल गए।

क्या है मामला?

झूंसी क्षेत्र के पालीकरनपुर छिबैया निवासी श्रीमती शिवर्तिका के बैंक खाते से 17 मार्च 2026 को साइबर ठगों ने धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

शिकायत मिलते ही साइबर हेल्प डेस्क, थाना झूंसी ने तत्परता दिखाते हुए ठगी गई पूरी राशि को समय रहते होल्ड करा दिया। इसके बाद लगातार फॉलोअप करते हुए 30 मार्च, सोमवार को पूरी धनराशि सफलतापूर्वक पीड़िता के खाते में वापस करा दी गई।

परिवार में लौटी खुशियां

अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने पर पीड़िता और उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने झूंसी पुलिस की इस सराहनीय कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।

जरूरी सलाह

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें (24 घंटे के भीतर) या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

पुलिस टीम

इस सराहनीय कार्य में शामिल पुलिस टीम में उपनिरीक्षक नवतीत कुमार, उपनिरीक्षक अखिल ओझा, कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार यादव और कांस्टेबल दीपचंद्र पाल ने सक्रिय भूमिका निभाई।

मिशन शक्ति के तहत नवरात्रि मेले में गुम 6 वर्षीय ओमप्रकाश को महिला थाना ने फुर्ती से बरामद कर परिजनों को सौंपा, जनता ने की पुलिस की तारीफ

(एजेंसी)।

पीलीभीत, 30 मार्च 2026: उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति फेज-5 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चल रहे व्यापक अभियान की एक मिसाल कायम करते हुए महिला थाना की टीम ने यशवंतरी देवी देवी मंदिर परिसर में आयोजित नवरात्रि मेले में गुम हुए करीब 6 वर्षीय बालक ओमप्रकाश को सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता के हवाले कर दिया। मेले में उमड़ती भिड़भांट के बीच पुलिस की फुर्ती भरी कार्रवाई ने अभिभावकों व स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया।जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यशवंतरी देवी मंदिर में रंग-बिरंगे नवरात्रि मेले का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान श्रीमती भगवती पत्नी लक्ष्मण प्रताप निवासी मोहल्ला मिश्रनटोला, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत अपने 6 वर्षीय पुत्र ओमप्रकाश के साथ मेले में घूमने आईं। भीड़भाड़ में बालक गुम हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया।महिला थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन विशेष टीमों का गठन किया। टीमों ने मेले परिसर में लगे लाउडस्पीकरों के जरिए जगह-जगह अनाउंसमेंट कराई तथा संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस के अथक प्रयासों का फलस्वरूप कुछ ही समय में बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया। उसके माता-पिता को सौंपते हुए पुलिस ने उन्हें सतर्क रहने की नसीहत भी दी।इस कार्य में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता कुमारी, उपनिरीक्षक श्री रघुनाथ, महिला हेल्पडेस्क प्रियांशी तथा महिला पीआरडी सावित्री की अहम भूमिका रही। आमजनमानस ने सोशल मीडिया पर पुलिस टीम की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए वायरल पोस्ट साझा कीं। महिला थाना ने अपील की है कि मेले व सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों पर नजर रखें तथा संदिग्ध स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल करें।

अमृत सरोवर बना भ्रष्टाचार का अड्डा! नवदिया मरौरी में बिना काम के हड़पी गई लाखों की रकम

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा भारतीय किसान यूनियन(भाकियू) का लिया सहारा

(एजेंसी)।

बिलसंडा (पीलीभीत)।ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवदिया मरौरी में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान ममता देवी के पति और ससुर ने अमृत सरोवर सहित अन्य विकास कार्यों में बिना कार्य कराए ही ग्राम निधि खाते से भारी धनराशि निकाल ली।ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में विकास कार्य पूरे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता। अमृत सरोवर योजना, जो गांव के जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई थी, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन हर बार मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इससे नाराज ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।अब परेशान होकर ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेताओं का सहारा लिया है। भाकियू नेताओं के माध्यम से मामले को उजागर कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है।ग्रामीणों का आरोप है कि पिता-पुत्र की मिलीभगत से ग्राम निधि खाते से अवैध रूप से बड़ी रकम निकाली गई है। यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो करोड़ों के घोटाले का खुलासा हो सकता है।ग्रामीणों की मांगःपूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो ग्राम निधि की निकासी का ऑडिट कराया जाए दोषियों से धनराशि की वसूली हो अब बड़ा सवालःक्या प्रशासन इस बार भी मामले को दबा देगा या फिर भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई? यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ग्रामीण विकास की सच्चाई भी उजागर करता है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है।

बीसलपुर में पूर्व मंत्री बाबू तेज बहादुर गंगवार के नाम पर प्रेरणा स्थल और पार्क बनेगाः भाजपा नेता रत्नेश गंगवार की घोषणा

(एजेंसी)।

पीलीभीत /बीसलपुर के भाजपा वरिष्ठ नेता रत्नेश गंगवार ने विकास पुरुष स्वर्गीय श्री बाबू तेज बहादुर गंगवार जी (पूर्व मंत्री एवं विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार) के नाम पर नगर पालिका बीसलपुर में एक प्रेरणा स्थल और पार्क का निर्माण कराने की घोषणा की है।

रत्नेश गंगवार ने कहा, "इसके लिए मैं सरकार से हर स्तर पर मांग करूंगा और अपने पास से भी बड़ा सहयोग दूंगा। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। आप सभी का समर्थन चाहिए।" उन्होंने जनता से इस पहल में सहयोग की अपील की। बाबू तेज बहादुर गंगवार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, और यह प्रेरणा स्थल उनकी स्मृति को अमर रखेगा।

स्थानीय लोगों में उत्साह

स्थानीय निवासियों ने इस घोषणा का जोरदार स्वागत किया है। बीसलपुर के कई प्रमुख नागरिकों ने बताया कि बाबू तेज बहादुर गंगवार ने अपने कार्यकाल में सड़कें, जल आपूर्ति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया था। एक बुजुर्ग निवासी रामस्वरूप ने कहा, "यह पार्क न केवल उनकी याद दिलाएगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। हम रत्नेश जी के इस प्रयास का पूरा साथ देंगे।"

सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को अन्य देशों के साथ मजबूत करने की पहल

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय, सांस्कृतिक समझौतों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापनों आदि के माध्यम से अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता है। मंत्रालय जी20, ब्रिक्स, एससीओ, सार्क आदि जैसे बहुपक्षीय सांस्कृतिक मंचों का आयोजन और उनमें भागीदारी भी करता है। मंत्रालय वैश्विक सहभागिता योजना का संचालन भी करता है, जिसके इसके अंतर्गत विदेशों में भारत के त्योहारों का आयोजन किया जाता है और भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेश स्थित भारत-विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समितियों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के अधीन एक संगठन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) भी विदेशों में अपने सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल भंडार में पांडुलिपियों को पुनः खोजकर, संरक्षित करके, डिजिटल रूप में परिवर्तित करके और साझा करके, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के जीवंत स्रोत के रूप में "ज्ञान भारतम" नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य व्यवस्थित सर्वेक्षण और प्रलेखन, वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रकाशन के साथ-साथ एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (एनडीआर) की स्थापना के माध्यम से भारत की पांडुलिपि विरासत की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है, ताकि अनुसंधान, शिक्षा और जन भागीदारी के लिए इसकी सुलभता सुनिश्चित हो सके।

आईसीसीआर अन्य देशों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालित करता है। यह विदेशों में स्थित दूतावासों/पोस्टों के परामर्श से विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन के चेयर स्थापित करता है।

सरकार और आरबीआई के उपायों से ग्रामीण निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित हुआ

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में निरंतर वृद्धि से कृषि, एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों को समर्थन मिला

(जीएनएस)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और बाजार दरों तक इसका लाभ मजबूती से पहुंच सके।

सरकार ने स्वयं सहायता समूहों सहित ग्रामीण विकास पहलों के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को जारी किए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देश और सरकार द्वारा बैंकों के लिए निर्धारित जमीनी स्तर संबंधी कृषि ऋण (जीएलसी) लक्ष्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के दायरे को बढ़ाने तथा किसानों को संस्थागत ऋण सुदृढ़ करने के प्रमुख नीतिगत साधनों के रूप में कार्य करते हैं।

आरबीआई द्वारा जारी पीएसएल दिशानिदेर्शों के अनुसार वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा वे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), जो वेतनभोगी बैंकों की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण या ऑफ-बैलेंस शीट जोखिमों के ऋण समतुल्य, जो भी अधिक हो, का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आवंटित करना अनिवार्य है। इसमें से 10 प्रतिशत का उप-लक्ष्य लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए निर्धारित है। साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र में आरआरबी क्रेडिट पुनर्वित्त निधि

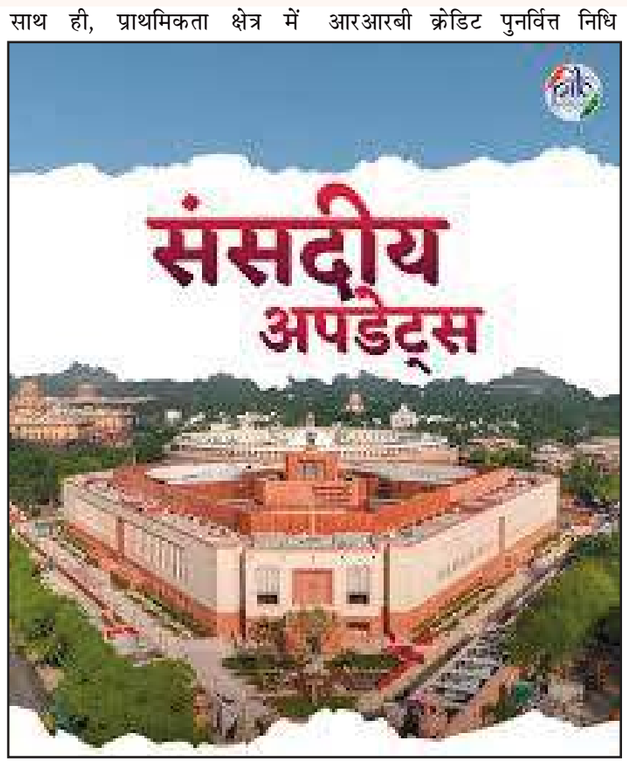

अपेक्षाकृत कम ऋण प्रवाह वाले जिलों (जिनमें कृषि एवं लघु/सीमांत किसानों को ऋण भी शामिल हैं) के लिए प्रोत्साहन ढांचा तथा अपेक्षाकृत ऋण प्रवाह जिलों के लिए निरूत्साहन ढांचा भी निर्धारित किया गया है, ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का अधिक संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 1 जनवरी, 2025 से संबद्ध गतिविधियों सहित संपार्श्विक मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण की सीमा 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रति उधारकर्ता कर दी गई है।

पीएसएल की कमी से निर्मित विभिन्न निधियों जैसे अल्पकालिक सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (एसटीसीआरसीएफ), अल्पकालिक (एसटीआरआरबीएफ) और दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) के माध्यम से पात्र ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) को रियायती पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

नाबार्ड (एनएबीएआरडी) स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है :

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म/ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण सहायता।

"एम-सुविधा" के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कौशल उन्नयन।

नाबार्ड के वित्तीय समावेशन कोष (एफआईएफ) के माध्यम से सूक्ष्मवित्त ग्राहकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता।

जनजातीय विकास कार्यक्रम जिसके तहत एसएचजी गठन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिविर, सूक्ष्म उद्यम विकास पर प्रशिक्षण आदि गतिविधियों को सहायता दी जाती है।

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज

विकास की बड़ी योजनाएं

रत्नेश गंगवार ने प्रेरणा स्थल के अलावा पार्क में हरित क्षेत्र, वॉकिंग ट्रैक, योगा जोन और बच्चों के खेल मैदान जैसी सुविधाएं विकसित करने की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि यह परियोजना अगले छह महीनों में शुरू हो जाएगी। इसके लिए वे नगर पालिका, जिला प्रशासन और विधायक के साथ मिलकर काम करेंगे। रत्नेश गंगवार ने कहा, "बीसलपुर को एक आदर्श पर्यटन और विश्राम स्थल बनाना मेरा सपना है।"

स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल को पार्टी की विकासोन्मुखी सोच का प्रतीक बताया। अधिक जानकारी के लिए रत्नेश गंगवार से संपर्क करें।

सीएसआईआर ने स्वदेशी बायो-बिटुमेन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया: कृषि अवशेषों को टिकाऊ सड़कों में परिवर्तित करना

(जीएनएस)।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने सतत और चक्रीय अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए अपनी नवोन्मेषी तकनीक "लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायो-बिटुमेन - कृषि अवशेष से सड़कों तक" के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह; सीएसआईआर की महानिदेशक एवं डीएसआईआर की सचिव डॉ. (श्रीमती) एन. कलैसेल्वी के अलावा, मंत्रालयों, सीएसआईआर संस्थानों, उद्योग जगत के हितधारकों और नीति निमार्ता क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जैव-बिटुमेन प्रौद्योगिकी के विकास को एक 'ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम' बताया, जो कृषि को अवसंरचना और नवाचार से जोड़ता है। श्री चौहान ने कहा कि जैव-बिटुमेन को अपनाना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, नेट जीरो लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था ढांचे जैसी प्रमुख पहलों के अनुरूप है। उच्च मूल्य वाली अवसंरचना परियोजनाओं में कृषि अवशेषों का उपयोग किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करता है और पराली जलाने तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया कि यह पहल आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और "अपशिष्ट से धन" के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि यह तकनीक कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना विकास सहित कई क्षेत्रों के प्रभावी समन्वय को प्रदर्शित करती है, जिसे मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा कि जैव-बिटुमेन तकनीक ने स्थायित्व, पारंपरिक बिटुमेन के साथ अनुकूलता और कम कार्बन उत्सर्जन के मामले में आशाजनक प्रदर्शन किया है।

जो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त बनाता है।

डॉ. एन. कलैसेल्वी ने कहा कि यह विकास पेट्रोलियम आधारित सामग्रियों से जैव आधारित सामग्रियों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए नियमित प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के प्रति सीएसआईआर की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)